

अनिरुद्ध प्रसाद

बनाम

राजेश्वरी सरोज दास और अन्य

अप्रैल 20, 1976

[वाई. वी. चंद्रचूड़, वी. आर. कृष्णा अय्यर और ए. सी. गुप्ता, न्यायमूर्तिगण]

चुनाव — जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 — धारा 97 — प्रत्युत्तरात्मक याचिका
— स्वरूप एवं क्षेत्र — चुनाव संचालन नियम, 1961 — नियम 73(2)(डी) — पहचान चिह्न
युक्त मतपत्र

19 व्यक्तियों ने 11 रिक्तियों को भरने के लिए बिहार-विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव लड़े। अपीलार्थी और उत्तरदाता संख्या 1 से 10 को सफल उम्मीदवार घोषित किया गया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा चुनाव आयोजित किया गया था। मतों की गिनती निर्वाचन आचरण नियम 1961 के कंडिका 7 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ा गया था। निर्वाचन अधिकारी ने 9 मतपत्रों को अस्वीकार कर दिया और 306 को स्वीकार कर लिया। निर्वाचन अधिकारी ने नियम 6 के आवेदन द्वारा किसी उम्मीदवार की वापसी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मतों का न्यूनतम कोटा 2551 निर्धारित किया। पहले तीन दौर में 1 से 7 उत्तरदाताओं को निर्वाचित घोषित किया गया था। चौथे चरण में किसी भी उम्मीदवार को सफल घोषित नहीं किया जा सका। पाँचवें और छठे दौर में 8 और 9 को निर्वाचित घोषित किया गया। सातवें दौर में, उत्तरदाता संख्या 18 (चुनाव याचिकाकर्ता) को हटा दिया गया और अंतिम दौर में, यानी 8वें दौर में, अपीलार्थी और उत्तरदाता संख्या 10 को सफल उम्मीदवार घोषित किया गया।

उत्तरदाता संख्या 18 ने सफल उम्मीदवारों के चुनाव को इस आधार पर चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की कि उसके पक्ष में प्रथम वरीयता वाले 3

मतपत्रों की अस्वीकृति, उत्तरदाता संख्या 9 के पक्ष में प्रथम वरीयता वाले 2 मतपत्रों की अस्वीकृति, विचार संख्या 8 के पक्ष में प्रथम वरीयता वाले एक मतपत्र की अवैध स्वीकृति और चौथे दौर की गिनती में मतों की गलत गिनती ने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया था। निर्वाचन अधिकारी ने एक मतपत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इसमें केवल एक क्षैतिज रेखा है, दूसरा इस आधार पर कि इसमें एक कमजोर निशान है और तीसरा इस आधार पर कि मतदाता ने एक उम्मीदवार के पक्ष में चौथी वरीयता के वोट के माध्यम से अंक प्राप्त किए थे और इसे दूसरे को सौंपा था। उत्तरदाता संख्या 8 और कुछ अन्य उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय में उपस्थिति दर्ज नहीं की। उत्तरदाता संख्या 9 ने एक लिखित बयान के साथ-साथ अभियोग याचिका भी दायर की। उन्होंने माना कि निर्वाचन अधिकारी ने 2 मतपत्रों को गलत तरीके से खारिज कर दिया था, जिसमें उनके पक्ष में पहली वरीयता के वोट थे और एक अन्य मतपत्र में उनकी ओर से दूसरी वरीयता के वोट थे। अपीलार्थी, जो उच्च न्यायालय में उत्तरदाता संख्या 10 था, ने याचिका का विरोध किया। उच्च न्यायालय ने पार्टियों की सहमति के साथ प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय लिया कि क्या चुनाव याचिका बनाए रखने योग्य थी और क्या निर्वाचन अधिकारी ने गलत तरीके से और अवैध रूप से मतपत्रों को अस्वीकार कर दिया था और यदि ऐसा है, तो क्या चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि तीन विवादित मतपत्रों में चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 73 (2) (डी) के अर्थ के भीतर कोई पहचान चिह्न नहीं थे और इसलिए, निर्वाचन अधिकारी ने उन मतपत्रों को अमान्य बताते हुए गलती की थी। उच्च न्यायालय के समक्ष इस बात पर विवाद किया गया कि यदि गलत तरीके से खारिज किए गए 3 मतपत्रों को समाप्त नहीं किया जाता तो उत्तरदाता संख्या 18 को निर्वाचित घोषित किया जाता। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि चुनाव याचिकाकर्ता का चुनाव 3 मतपत्र की अस्वीकृति से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि तीन मतों की अवैध अस्वीकृति

के परिणामस्वरूप उत्तरदाता संख्या 9 पर छठे दौर तक मुकदमा चलाने की आवश्यकता थी और लेकिन गलत अस्वीकृति के लिए उत्तरदाता संख्या 9 को पहले दौर में ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता। मुद्दा संख्या 1,2 और 3 पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के खिलाफ इस न्यायालय में चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर पलायन याचिका द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया था।

इसके बाद, उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका पर आगे बढ़कर शेष मुद्दों पर सुनवाई की। अदालत द्वारा नियुक्त एक अधिकारी द्वारा पक्षों और उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में मतों की गिनती की गई। इसके बाद परिणाम पत्रक की एक उचित प्रति तैयार की गई, जिस पर सभी संबंधितों ने इसकी शुद्धता के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर किए। उच्च न्यायालय ने परिणामस्वरूप चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया, चुनाव याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित कर दिया और अपीलार्थी के चुनाव को रद्द कर दिया जिसने पुनः गिनती पर सबसे कम वोट प्राप्त किए थे।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा इसका प्रतिवाद किया गया था;

चूंकि उत्तरदाता संख्या 8 ने अभियोग याचिका दायर नहीं की थी, इसलिए उन्होंने मतपत्रों के तहत किसी भी लाभ का दावा करने से खुद को अलग कर लिया था, जिसे शुरू में निर्वाचन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन जिसे उच्च न्यायालय द्वारा वैध के रूप में स्वीकार कर लिया गया था।

अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 97 में प्रावधान है कि जब चुनाव याचिका में यह घोषणा करने की मांग की जाती है कि निर्वाचित उम्मीदवार के अलावा कोई अन्य उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित हो गया है तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य पक्ष यह साबित करने के लिए सबूत दे सकता है कि ऐसे उम्मीदवार का चुनाव अमान्य होता अगर वह निर्वाचित उम्मीदवार होते और उनके चुनाव पर सवाल उठाते हुए

एक याचिका प्रस्तुत की गई होती। उक्त धारा के परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचित उम्मीदवार या ऐसा अन्य पक्ष तब तक ऐसा साक्ष्य देने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसे मुकदमा शुरू होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय को ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना नहीं दी गई हो। धारा 97 तब लागू होती है जब निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने वाला एक समग्र दावा किया जाता है और घोषणा की जाती है कि किसी अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए। उस मामले में निर्वाचित उम्मीदवार उस व्यक्ति के खिलाफ अभियोग करता है जिसके पक्ष में घोषणा का दावा किया जाता है। अपने स्वयं के चुनाव में बचाव की अभियोग याचिका सच्चाई और सार में इतनी अधिक याचिका नहीं है, हालांकि यह इसका अंतिम उद्देश्य और प्रभाव है, हमले की याचिका के रूप में जिसके द्वारा एक सफल उम्मीदवार प्रति-याचिकाकर्ता की भूमिका ग्रहण करता है और तर्क देता है कि जिस उम्मीदवार के पक्ष में घोषणा का दावा किया जाता है, उसका चुनाव अमान्य होता यदि निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके चुनाव को प्रश्नगत बताते हुए एक याचिका प्रस्तुत की गई होती। चूंकि चुनाव याचिकाकर्ता ने एक समग्र राहत के लिए कहा था, इसलिए धारा 97 को आकर्षित करने के लिए आवश्यक शर्तें निस्संदेह मौजूद थीं। हालांकि, अपीलार्थी का तर्क पूरी तरह से एक अलग प्रकार का था। यह तर्क दिया गया था कि उत्तरदाता संख्या 8 बिना किसी अभियोग याचिका के अपने पक्ष में डाले गए प्रथम वरीयता मतों का लाभ नहीं उठा सकता है। यह विवाद धारा 97 के दायरे से बाहर है, क्योंकि पहली वरीयता के मत का दावा करने में उत्तरदाता संख्या 8 किसी भी तरह से चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए और गिने गए किसी भी मत की वैधता या चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से अपने चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए किसी भी कदम को चुनौती नहीं देता है। उत्तरदाता संख्या 8 ने कोई विवाद नहीं किया और चुनाव याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में कुछ भी नहीं करना चाहते थे कि उन्हें निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए। चुनाव याचिकाकर्ता और उत्तरदाता संख्या 8 के बीच इस सवाल पर हितों

का कोई टकराव नहीं था कि क्या विशेष वोट को उत्तरार्द्ध के पक्ष में गिना जाना चाहिए। यदि विचाराधीन 3 मतपत्र वैध थे तो उन्हें सभी उद्देश्यों के लिए वैध माना जाना चाहिए और इसलिए, उन मतपत्रों के तहत उत्तरदाता संख्या 8 के पक्ष में डाले गए मतों को उनके पक्ष में गिना जाना चाहिए। [97 सी, 98 ए, डी-एफ, 99-डी]

जबर सिंह बनाम गेंदा लाल [1964] 6 एस.सी.आर.-54, प्रतिष्ठित।

दीवानी अपील्य क्षेत्राधिकार : 1975 की दीवानी अपील सं. 714।

चुनाव याचिका सं. 2/74 में पटना उच्च न्यायालय के 18 अप्रैल 1975 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए प्रमोद स्वरूप और के. के. चौधरी।

उत्तरदाताओं संख्या 8 और 9 के लिए केपी वर्मा, बी. बी. सिन्हा और एस. सी. पटेल।
जे. पी. गोयल और एम. पी. मुखर्जी; उत्तरदाता संख्या 18 के लिए।

श्री पाल सिंह; उत्तरदाताओं संख्या 10 , 12 और 17 के लिए ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था —

चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति — बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में उन्नीस व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा जो 11 रिक्तियों को भरने के लिए 29 मार्च, 1974 को आयोजित किए गए थे। अपीलार्थी अनिरुद्ध प्रसाद और उत्तरदाता 1 से 10 को सफल उम्मीदवार घोषित किया गया।

चुनाव आनुपातिक रूप से एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा पुनः प्रस्तुत करने की प्रणाली द्वारा आयोजित किए जाने के कारण, मतों की गिनती निर्वाचन आचरण नियम, 1961 (जिसे इसके बाद नियम कहा जाता है) के भाग VII में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की गई थी, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ा गया था। निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले बिहार विधान सभा के सचिव ने 9 मतपत्रों को खारिज कर दिया और शेष 306 मतपत्रों को वैध स्वीकार कर लिया। यह देखते हुए कि 11 सीटों को 306 मतपत्रों में डाले गए मतों के

आधार पर भरा जाना था, निर्वाचन अधिकारी ने नियम 76 के आवेदन द्वारा 2551 मतों का न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जो एक कैंडी-डेट की वापसी को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त था। समय-समय पर गिनती के दौरान, तकनीकी अंकगणितीय सूत्र लागू किए गए थे इसी तरह मतों को जोड़ा जाता था और गिनती के एक दौर से दूसरे दौर में घटाया जाता था और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस उद्देश्य के लिए नियमों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सरल प्रक्रिया का परिणाम दर्ज किया जाता था।

गिनती के पहले दौर में, 1 से 5 उत्तरदाताओं को निर्वाचित घोषित किया गया क्योंकि उन्होंने 2551 के निर्धारित कोटे से अधिक वोट प्राप्त किए। गणना के दूसरे और तीसरे दौर में, अधिशेष मतों के हस्तांतरण के आधार पर उत्तरदाता 6 (अब मृतक) और उत्तरदाता 7 को सफल घोषित किया गया। चौथे दौर में किसी भी उम्मीदवार को सफल घोषित नहीं किया जा सका, लेकिन पांचवें दौर में उत्तरदाता 8 और 9 और छठे दौर में उत्तरदाता 9 को निर्वाचित घोषित किया गया। गिनती के सातवें दौर में उत्तरदाता 18 (इंद्र कुमार) को बाहर कर दिया गया और आठवें दौर में, जो गिनती का अंतिम दौर था, अपीलार्थी अनिरुद्ध प्रसाद और उत्तरदाता 10 को सफल उम्मीदवार घोषित किया गया।

उत्तरदाता 18 ने जमीनी स्तर पर सफल उम्मीदवारों के चुनाव को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की कि प्रथम वरीयता वाले 3 मतपत्रों की अस्वीकृति, उत्तरदाता 9 के पक्ष में प्रथम वरीयता वाले 2 मतपत्रों की अस्वीकृति, उत्तरदाता 8 के पक्ष में प्रथम वरीयता वाले एक मतपत्र की अवैध स्वीकृति और चौथे दौर की गिनती में मतों की गलत गिनती ने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया था। उत्तरदाता सं. 18 के अनुसार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा गलत रूप से अस्वीकृत किए गए तीन मतपत्रों में से एक मतपत्र इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि उसमें एक छोटी क्षैतिज रेखा थी; दूसरा इस आधार पर कि उसमें एक हल्का-सा निशान था; और तीसरा इस आधार पर कि मतदाता ने एक प्रत्याशी के पक्ष में डाले गए चतुर्थ वरीयता मत को काट

दिया था और उसे किसी अन्य प्रत्याशी को आवंटित कर दिया था। इन तीनों मतपत्रों, जिनमें उत्तरदाता सं. 18 के पक्ष में प्रथम वरीयता मत अंकित थे, की अस्वीकृति आंशिक रूप से इस दृष्टिकोण पर आधारित थी कि मतदान करते समय संबंधित मतदाताओं ने ऐसे उपाय अपनाए थे जिनके माध्यम से उनकी पहचान की जा सकती थी। उत्तरदाता सं. 18 ने यह प्रार्थना की कि सफल प्रत्याशियों का चुनाव, अथवा पुनर्गणना पर न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी का चुनाव, शून्य घोषित किया जाए और उसे स्वयं विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाए। शेष सभी 18 प्रत्याशियों को निर्वाचन याचिका में उत्तरदाता के रूप में पक्षकार बनाया गया।

उत्तरदाता 1 से 6, 8 और 11 से 17 उच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उत्तरदाता 7 और 10 चुनाव याचिका में उपस्थित हुए और अपने लिखित बयान दाखिल किए। लेकिन उन्होंने आगे कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

उत्तरदाता 9, नाथूनी राम ने एक लिखित बयान और साथ ही एक अभियोग याचिका दायर किया। उन्होंने तर्क दिया कि निर्वाचन अधिकारी ने 2 मतपत्रों को गलत तरीके से खारिज कर दिया था, जिसमें उनके पक्ष में प्रथम वरीयता के वोट थे और एक अन्य मतपत्र में उनके पक्ष में द्वितीय वरीयता के वोट थे। उत्तरदाता 9 के अनुसार, भले ही चुनाव याचिका में उत्तरदाता 18 द्वारा की गई शिकायत वैध के रूप में स्वीकार किया गया, जो किसी भी दृष्टिकोण से उनके चुनाव को प्रभावित नहीं करेगा मामले में, वह अतिरिक्त वोटों का हकदार होगा जो गलत थे निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

अपीलार्थी अनिरुद्ध प्रसाद, जो उच्च न्यायालय में उत्तरदाता 10 थे, मामले में पेश हुए और अपना लिखित बयान दायर किया। उच्च न्यायालय ने उनके लिखित बयान को इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया कि उन्होंने चुनाव याचिका दायर करने वाले उत्तरदाता 18 और एकमात्र चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता उत्तरदाता 9 की लागत का भुगतान किया। यह शर्त उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर लगाई गई थी कि अपीलार्थी ने अपना लिखित बयान उस

उद्देश्य के लिए निर्धारित समय से बहुत पहले दाखिल किया था। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लागत का भुगतान नहीं किया और चूंकि लागत का भुगतान उनके लिखित बयान की स्वीकृति के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त थी, इसलिए उच्च न्यायालय ने लिखित बयान को अभिलेख पर लेने से इनकार करने का आदेश पारित किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के अधिवक्ता को चुनाव-याचिकाकर्ता द्वारा जाँच किए गए गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी और उत्तरदाता द्वारा 9. गवाहों द्वारा अपनी जाँच में दिए गए बयानों तक प्रति-परीक्षण को सीमित कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को खंडन के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने और मामले में साक्ष्यों पर तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति भी दी।

उत्तरदाता 18 द्वारा दायर चुनाव याचिका में निहित कथनों के आधार पर और लिखित बयान में निहित और उत्तरदाता 9 द्वारा दायर पुनरावेदन याचिका, उच्च न्यायालय ने निर्धारण के लिए 5 मुद्दे तैयार किए गए :

"1. क्या चुनाव याचिका, जैसा कि तैयार किया गया है, संधार्य है?

2. क्या मतगणना के समय निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में वैध रूप से डाले गए तीन वोटों को प्रथम वरीयता के साथ अवैध और गलत तरीके से खारिज कर दिया? यदि हां, तो क्या इस कारण चुनाव परिणाम पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है?

3. क्या मतों की गिनती के समय निर्वाचन अधिकारी ने अवैध रूप से और गलत तरीके से दो मतों को अस्वीकार कर दिया था जिसमें पहली प्राथमिकता और दूसरी वरीयता के साथ एक मत वैध रूप से उत्तरदाता संख्या 9 के पक्ष में मतदान किया गया था? यदि ऐसा है तो इसका परिणाम यह है कि इससे चुनाव भौतिक रूप से प्रभावित हुआ?

4. क्या याचिकाकर्ता को वैध मतों का बहुमत प्राप्त हुआ है और क्या वह अपने दावे के अनुसार निर्वाचित घोषित होने का हकदार है?

5. याचिकाकर्ता इस चुनाव याचिका में किस राहत, यदि कोई हो, का हकदार है?"

चूँकि मुद्दे 4 और 5 का निर्णय मुद्दों 1 से 3 के उत्तरों पर निर्भर करता था, इसलिए उच्च न्यायालय ने, प्रतिद्वंद्वी दलों की सहमति से, पहली बार में विचार के लिए मुद्दों 1 से 3 को लिया। इसके 28 फरवरी, 1975 के निर्णय के द्वारा इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव याचिका अभियोग थी और मुद्दा संख्या 1 पर अभिनिर्धारित किया कि याचिका बनाए रखने योग्य थी। इसने अंक संख्या 2 पर अभिनिर्धारित किया कि 3 विवादित मतपत्रों (प्रदर्श 4, 4/ए और 4/बी) में नियम 73 (2) (डी) के अर्थ के भीतर कोई पहचान चिह्न नहीं थे और इसलिए निर्वाचन अधिकारी ने उन मतपत्रों को अमान्य बताते हुए अस्वीकार कर दिया। उस स्तर पर उच्च न्यायालय के समक्ष यह विवादित नहीं था कि चुनाव याचिकाकर्ता (उत्तरदाता 18) को 2551 मतों का आवश्यक कोटा प्राप्त करने में विफल रहने के कारण गिनती के सातवें दौर में हटा दिया गया था और यदि प्रदर्श 4, 4/ए और 4/बी में निहित 3 प्रथम वरीयता मतों को उनके पक्ष में गिना जाता, तो उन्हें विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाता। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि चुनाव-याचिकाकर्ता का चुनाव 3 मतपत्रों की अस्वीकृति से प्रभावित हुए। तीसरे मुद्दे पर, उच्च न्यायालय के विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या 3 अन्य मतपत्र (प्रदर्श बी, बी/1 और बी/2) को निर्वाचन अधिकारी द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने 3 मतपत्रों को गलत तरीके से खारिज कर दिया था और इसमें उत्तरदाता 9 के पक्ष में डाले गए मतों को ध्यान में रखा जाना था। इन तीन मतपत्रों की गलत अस्वीकृति ने उत्तरदाता 9 के संबंध में चुनाव के परिणाम को काफी हद तक प्रभावित किया था इस अर्थ में है कि यदि 3 मतपत्रों में उनके पक्ष में डाले गए मतों को ध्यान में रखा जाता, तो उन्हें गिनती के पहले दौर में ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता और छठे दौर तक पीछे रहने की आवश्यकता नहीं होती। उच्च न्यायालय ने तदनुसार मुद्दा संख्या 3 पर अपना निष्कर्ष

दर्ज किया।

अपीलार्थी ने 28 फरवरी, 1975 के उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर की, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया।

इसके बाद उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका के साथ आगे बढ़कर शेष मुद्दों, 4 और 5 पर सुनवाई की। दलों की सहमति से इसने बिहार विधान परिषद के पूर्व उप सचिव श्री आर. एन. ठाकोर को मुद्दों संख्या 2 और 3 पर दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर वोटों की फिर से गिनती करने के लिए नियुक्त किया। श्री ठाकोर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के तहत वोटों की गिनती की जटिल प्रक्रिया से भली भांति परिचित थे। विद्वान अधिवक्ता जो चुनाव याचिकाकर्ता और उत्तरदाता 10 के लिए उच्च न्यायालय में पेश हुए वे विशेष प्रक्रिया से परिचित प्रतीत होते हैं और वे श्री ठाकोर की सहायता करने के लिए सहमत हुए। उत्तरदाता 9 इस बात पर सहमत हुए कि चुनाव याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उनकी ओर से प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। तदनुसार, श्री ठाकोर ने दलों और उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मतों की गिनती की। इसके बाद श्री ठाकोर ने उन पक्षों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में परिणाम पत्रक की एक उचित प्रति तैयार की, जिन्होंने इसकी शुद्धता के प्रतीक के रूप में उस पर अपने हस्ताक्षर किए।

निर्वाचन अधिकारी ने इस आधार पर चुनाव का परिणाम घोषित किया था कि केवल 306 मतपत्र वैध थे। उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी, 1975 के अपने फैसले में कहा गया कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा छह मतपत्रों को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वैध मतपत्रों की संख्या 306 से बढ़कर 312 हो गई। परिणामस्वरूप न्यूनतम कोटा 2551 से बढ़कर 2601 हो गया। श्री ठाकोर द्वारा किए गए मतों की फिर से गिनती के आधार पर, उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया और उत्तरदाता 1 से 10 और उत्तरदाता 18 (चुनाव याचिकाकर्ता) को सफल उम्मीदवार घोषित कर दिया। अपीलार्थी

अनिरुद्ध प्रसाद, जो उच्च न्यायालय में उत्तरदाता 10 थे और जिन्हें निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया था, को मतों की फिर से गिनती पर, उत्तरदाता 18 द्वारा प्राप्त 2579 मतों के मुकाबले 2500 मत प्राप्त करते हुए पाया गया। उच्च न्यायालय ने सबसे कम मत प्राप्त करने वाले अपीलार्थी के चुनाव को रद्द कर दिया। यह 18 अप्रैल, 1975 के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील का निर्देश दिया गया है।

उच्च न्यायालय के प्रारंभिक निष्कर्ष के बाद कि छह मतपत्रों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था और वे मतपत्र वैध थे, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन किया कि चूंकि उत्तरदाता 8, जनार्दन प्रसाद वरना ने कोई अभियोग दायर नहीं किया था, इसलिए मतपत्र प्रदर्श बी/2 के तहत उनके पक्ष में डाले गए प्रथम वरीयता वोट और प्रदर्श बी और बी/1 के तहत उनके पक्ष में डाले गए सातवें वरीयता वोट को उनकी गिनती में नहीं गिना जाना चाहिए। 14 अप्रैल, 1975 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उस आवेदन को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि मतपत्रों में निहित और उसके तहत डाले गए सभी वोट जो वैध माने गए थे, उन्हें संबंधित नियमों के अनुसार संबंधित उम्मीदवारों के पक्ष में गिना जाना चाहिए।

अपीलार्थी की ओर से पेश हुए श्री प्रमोद स्वरूप ने एक जोरदार याचिका दायर की कि चूंकि उत्तरदाता 8 ने अभियोग याचिका दायर नहीं की थी, इसलिए उन्होंने मतपत्रों के तहत किसी भी लाभ का दावा करने से खुद को वंचित कर दिया था, जिन्हें शुरू में निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था, लेकिन जिन्हें उच्च न्यायालय ने वैध मानते हुए स्वीकार कर लिया था। यह याद किया जा सकता है कि चुनाव याचिकाकर्ता ने केवल तीन मतपत्रों (प्रदर्श 4, 4/ए और 4/बी) की जांच और स्वीकृति की मांग की थी, जिनमें उसने प्रथम वरीयता वोट प्राप्त किए थे। उत्तरदाता 9 ने अधिनियम की धारा 97 के तहत एक अभियोग दायर किया दो अन्य मतपत्रों, बी और बी/1 को प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है, जिसमें उन्होंने पहली वरीयता के वोट प्राप्त किए थे और बैलेट पेपर, प्रदर्श बी/2, जिसमें उन्होंने

दूसरी वरीयता प्राप्त की थी, की फिर से जांच की जानी चाहिए और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ये छह मतपत्र जिन्हें निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा वैध स्वीकार कर लिया गया। उत्तरदाता 8 द्वारा अभियोग दायर करने में विफलता पर जोर देने के अलावा, अपीलार्थी की शिकायत यह है : प्रदर्श बी/2 जिसमें उत्तरदाता 8 के लिए पहली वरीयता वाला वोट शामिल है उत्तरदाता 9 द्वारा प्राप्त मतों की गिनती के लिए भी विचार नहीं किया गया था, जिन्होंने अपना अभियोग दायर किया था और जिनके कहने पर प्रदर्श बी/2 को वैध माना गया था; क्योंकि, निर्वाचित होने के लिए उत्तरदाता 9 के लिए प्रदर्श बी और बी/1 के तहत उसके पक्ष में डाले गए पहली वरीयता के मतों पर भरोसा करना पर्याप्त था। प्रदर्श बी/2 के तहत उनके पक्ष में डाला गया द्वितीय वरीयता वोट उनके चुनाव के लिए अनावश्यक था। अपीलार्थी के अनुसार, यह विसंगतिपूर्ण है कि उत्तरदाता 8 जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में कोई भाग नहीं लिया था, उसे प्रदर्श बी/2 के तहत उसके पक्ष में डाले गए प्रथम वरीयता मत का लाभ मिलना चाहिए, जब उसने ऐसी कोई राहत नहीं मांगी, विशेषकर तब जब उत्तरदाता 9, जिसके कहने पर विशेष मतपत्र को वैध माना गया था, ने अपने चुनाव के लिए अपने पक्ष में डाले गए द्वितीय वरीयता मत को जोड़ने की आवश्यकता नहीं जताई थी।

यह तर्क अधिनियम की धारा 97 में निहित प्रावधानों पर आधारित है, जो इस न्यायालय के कई फैसलों का विषय रहा है। उस खंड में कहा गया है :

"97. जब सीट का दावा किया जाता है तो अभियोग।- (1) जब किसी निर्वाचन याचिका में यह घोषणा मांगी जाती है कि निर्वाचित प्रत्याशी के अतिरिक्त कोई अन्य प्रत्याशी विधिवत निर्वाचित हुआ है, तो निर्वाचित प्रत्याशी या कोई अन्य पक्षकार यह साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है कि यदि वह प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किया गया होता और उसकी निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका प्रस्तुत की गई होती, तो उसका निर्वाचन अमान्य ठहराया गया होता।

बशर्ते कि निर्वाचित उम्मीदवार या ऐसा अन्य पक्ष, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसा साक्ष्य देने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह परीक्षण प्रारंभ होने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर न हो, उच्च न्यायालय को उसके ऐसा करने के इरादे की सूचना दी गई है और उसने क्रमशः धारा 117 और 118 में निर्दिष्ट सुरक्षा और आगे की सुरक्षा भी दी है।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक सूचना के साथ वही कथन तथा विवरण संलग्न होंगे, जो निर्वाचन याचिका के मामले में धारा 83 के अंतर्गत अपेक्षित हैं, और वह उसी प्रकार हस्ताक्षरित तथा सत्यापित की जाएगी।

एक चुनाव-याचिकाकर्ता या तो अधिनियम की धारा 100 के तहत राहत की मांग कर सकता है कि निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए या वह धारा 101 के तहत अतिरिक्त राहत की मांग कर सकता है कि उसे या किसी अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाए। यह केवल तभी है जब ऐसा समग्र दावा किया जाता है कि धारा 97 आकर्षित होती है। निर्वाचित उम्मीदवार तब उस व्यक्ति के खिलाफ फिर से आरोप लगा सकता है जिसके पक्ष में धारा 101 के तहत घोषणा का दावा किया जाता है। अभियोगकारी याचिका सच्चाई और सार में अपने स्वयं के चुनाव के बचाव में एक याचिका नहीं है, हालांकि यह इसका अंतिम उद्देश्य और प्रभाव है, हमले की याचिका के रूप में जिसके द्वारा सफल उम्मीदवार एक प्रति-याचिकाकर्ता की भूमिका ग्रहण करता है और तर्क देता है कि जिस उम्मीदवार के पक्ष में घोषणा का दावा किया जाता है, उसका चुनाव अमान्य होता यदि निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके एच चुनाव को प्रश्न में रखते हुए एक याचिका प्रस्तुत की गई होती। चूंकि चुनाव याचिका दायर करने वाले उत्तरदाता 18 ने एक समग्र राहत की मांग की थी कि उस उम्मीदवार या सफल उम्मीदवारों का चुनाव, जिसने कम से कम मत प्राप्त किये को अलग रखा जाना चाहिए और उन्हें स्वयं एक सफल उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए, धारा 97 को आकर्षित करने के लिए आवश्यक शर्तें निस्संदेह मौजूद थीं।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी सफल उम्मीदवार या अन्य पक्ष द्वारा किए गए प्रत्येक तर्क को तब तक प्रतिबंधित किया जाता है जब तक कि एक अभियोग याचिका दायर नहीं की जाती है। अभियोग की याचिका धारा 97 के तहत चुनाव-याचिकाकर्ता के दावे के लिए जाती है कि उसे या सफल उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है, पुनर्निर्देशक की याचिका यह है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में घोषणा का दावा किया गया है, उसका चुनाव अमान्य होता यदि निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके चुनाव को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की गई होती। उदाहरण के लिए, कोई भी सफल उम्मीदवार एक अभियोग याचिका द्वारा तर्क दे सकता है कि चुनाव का चुनाव-याचिकाकर्ता, यदि वह सफल होता है, तो दोषों से पीड़ित होता है जिसके कारण यह अमान्य होगा। इस तरह की चुनौती केवल एक अभियोग याचिका द्वारा दी जा सकती है और जब तक कि ऐसी याचिका धारा 97 के साथ दायर नहीं की जाती है, तब तक सफल उम्मीदवार या किसी अन्य पक्ष के लिए चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अतिरिक्त दावे को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।

हमारे सामने अपीलार्थी का तर्क पूरी तरह से अलग प्रकार का है। यह तर्क दिया जाता है कि उत्तरदाता 8 बिना किसी प्रतिवाद याचिका के प्रदर्श बी/2 के तहत अपने पक्ष में डाले गए प्रथम वरीयता मत का लाभ नहीं उठा सकता। यह विवाद धारा 97 के दायरे से बाहर है क्योंकि, प्रदर्श बी/2 के तहत पहली वरीयता वोट का दावा करने में उत्तरदाता 8 किसी भी तरह से चुनाव-याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए और गिने गए किसी भी वोट की वैधता या चुनाव-याचिकाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से अपने चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए किसी भी कदम को चुनौती नहीं देता है। वास्तव में, उत्तरदाता संख्या 8 ने कोई आपत्ति नहीं उठाई और न ही वह यह उठाना चाहता था कि निर्वाचन-याचिकाकर्ता के इस दावे के संबंध में कि उसे निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए। यह निर्वाचन 11 सीटों के लिए था और प्रदर्श बी/2 में प्रथम वरीयता मत के संबंध में उत्तरदाता संख्या 8 का दावा, निर्वाचन-

याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार के प्रतिकूल नहीं था, जिसने समग्र राहत की मांग की थी। यह तथ्य ही कि प्रथम वरीयता मत की गणना उत्तरदाता संख्या 8 के पक्ष में किए जाने के बावजूद निर्वाचन-याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय में सफल हुआ, यह दर्शाता है कि इस प्रश्न पर कि उक्त मत उत्तरदाता संख्या 8 के पक्ष में गिना जाना चाहिए या नहीं निर्वाचन-याचिकाकर्ता और उत्तरदाता संख्या 8 के बीच हितों का कोई टकराव नहीं था। प्रदर्श बी/2 में निहित प्रथम वरीयता मत के संबंध में उत्तरदाता संख्या 8 के दावे का यह प्रभाव नहीं पड़ा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कि निर्वाचन-याचिकाकर्ता के पक्ष में मूल रूप से गिने गए किसी भी मत को अमान्य ठहराया जाए। पुनः उल्लेख करना उपयुक्त है कि उत्तरदाता संख्या 8, अपीलकर्ता की तरह, सफल उम्मीदवारों में से एक था और यह उत्तरदाता संख्या 18 था, जिसे निर्वाचन में असफल घोषित किया गया था, जिसने निर्वाचन याचिका दायर की।

यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि विधान परिषद का निर्वाचन एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा किया गया था। उन्नीस उम्मीदवारों ने 11 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 76 से 85 तक मतों की गिनती के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करते हैं जब एक से अधिक सीटें भरी जानी होती हैं। नियम 76 के अनुसार, प्रत्येक वैध मतपत्र का मूल्य 100 माना जाता है और इसे सरल शब्दों में कहें तो किसी उम्मीदवार का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कोटा वैध मतपत्रों की संख्या को 100 से गुणा करके, कुल को भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या से एक से अधिक से विभाजित करके और भागफल में एक जोड़कर निर्धारित किया जाता है। प्रारंभ में, निर्वाचन अधिकारी द्वारा वैध के रूप में 306 मतपत्रों को स्वीकार किया गया था। तदनुसार न्यूनतम कोटा 2551 तय किया गया था : $(306 \times 100 = 30600 \div 11 + 1 = 2550 + 1 = 2551)$ । उच्च न्यायालय ने माना कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा 6 मतपत्रों को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप वैध मतपत्रों की संख्या बढ़कर 312 हो गई। तदनुसार न्यूनतम कोटा बढ़कर

2601 हो गया : $(312 \times 100 = 31200 \div 12 - 2600 + 1 = 2601)$)। न्यूनतम कोटा जो मुख्य रूप से वैध मतपत्रों के आधार पर तय किया जाता है, गणना और अधिशेष मतों के हस्तांतरण का प्रमुख बिंदु है। 'अधिशेष मत' का अर्थ है न्यूनतम कोटे से अधिक मत और यह ऐसे अधिशेष मत हैं जो मैदान में बचे अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित किए जाते हैं। विभिन्न नियम और उनके कार्य, जैसा कि नियमों की अनुसूची में दर्शाया गया है, यह दर्शाते हैं कि एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में मतों की गिनती की एक प्रगतिशील अंतर-संबद्ध विधि शामिल है। इसलिए अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि एक मतपत्र को न्यूनतम निर्धारित करने के लिए वैध माना जा सकता है लेकिन किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की गिनती के उद्देश्यों के लिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। यदि मतपत्र प्रदर्श बी/2 वैध है, इसे सभी उद्देश्यों के लिए वैध माना जाना चाहिए और इसलिए उत्तरदाता 8 के पक्ष में उसमें निहित पहली वरीयता वोट को उसके पक्ष में गिना जाना चाहिए। यह विशेष रूप से तब होगा जब प्रक्रिया में उत्तरदाता 8 और अपीलार्थी के बीच कोई अभियोग शामिल नहीं हो सकता है, जो दोनों सफल उम्मीदवार थे। और वास्तव में ऐसी गिनती में उत्तरदाता 8 और चुनाव याचिकाकर्ता के बीच कोई आरोप-प्रत्यारोप शामिल नहीं है, जिसे पहले ही कहा जा चुका है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम वरीयता वोट की गिनती के बावजूद उत्तरदाता 8 के पक्ष में सफल घोषित किया गया था।

मामले के तथ्यों पर यह स्पष्ट है कि मूल रूप से, उत्तरदाता 8 ने अपीलार्थी द्वारा प्राप्त 2500 मतों के मुकाबले 2611 मत प्राप्त किए थे। प्रदर्श बी/2 के तहत उत्तरदाता 8 के पक्ष में डाले गए पहली वरीयता के वोट की गिनती किए बिना था। उस आधार पर भी अपीलार्थी उत्तरदाता 8 पर प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकता है और उसकी शिकायत कि उसे उत्तरदाता 8 के बजाय निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए, बिना किसी आधार के है।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने इस बात के समर्थन में *जबर सिंह बनाम गेंदा लाल*¹ (1) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत जोर दिया कि प्रतिवादी 8 बिना किसी प्रतिवाद याचिका के प्रदर्श बी/2 के तहत अपने पक्ष में डाले गए प्रथम वरीयता मत का लाभ नहीं उठा सकता।

यह एक विशिष्ट मामला था जिसमें सफल उम्मीदवार द्वारा उठाई जाने वाली आपत्ति को अधिनियम की धारा 97 के तहत प्रतिवाद याचिका के बिना नहीं उठाया जा सकता था। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी कि अपीलकर्ता के पक्ष में वोटों की अनुचित प्राप्ति हुई और स्वयं के संबंध में वोटों की अनुचित अस्वीकृति हुई। उत्तरदाता ने प्रार्थना की कि अपीलार्थी के चुनाव को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए और उसे स्वयं विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष आग्रह किया कि मतों की अनुचित अस्वीकृति और इस उत्तरदाता के पक्ष में मतों की अनुचित स्वीकृति हुई है। प्रतिवादी ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और इस न्यायालय ने इस आधार पर आपत्ति को स्वीकार किया कि प्रतिवादों के अभाव में अपीलकर्ता के लिए यह विशेष दलील उठाना उचित नहीं था। जैसा कि हमने पहले दिखाया है कि उत्तरदाता 8 ने यह तर्क नहीं दिया कि चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में या किसी अन्य उम्मीदवार के पक्ष में मतों का कोई अनुचित स्वागत किया गया था। धारा 97 के तहत उनके खिलाफ अभियोग दायर करने का कोई सवाल ही नहीं था। दूसरा, उस मामले में मतदान एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा नहीं था और गिनती की विशिष्ट प्रणाली के कारण उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का उस मामले में गिनती की योजना में कोई स्थान नहीं था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की ओर से उद्धृत अन्य निर्णयों पर चर्चा करना अनावश्यक प्रतीत होता है जो *धारा सिंह बनाम जिला न्यायाधीश, मेरठ और*

1 [1964] 6 एस. सी.आर. 54.

अन्य²; पी. मलाईचामी बनाम एम. एंडी अंबालम और अन्य³ और दीवानी अपील संख्या 83 1975 में दिया गया निर्णय, दिनांक 31 जुलाई, 1975 में बताए गए हैं। ये निर्णय उसी कारण से अलग किए जा सकते हैं जिसके लिए जबर सिंह का मामला तत्काल मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

इन कारणों से हम अपील को खारिज करते हैं और उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हैं लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका खारिज कर दी गई।

पीएच. पी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

2 [1968] 1 एस. सी. आर. 213

3 [1973] 3 एस. सी. आर. 1616